>

Title: Need to restore the commission for agents on Public Provident Fund and postal savings schemes.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं सरकार का ध्यान देश के लघु बचत में लगे लाखों एजेन्टों की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। श्यामला गोपीनाथ कमेटी की संस्तुति के आधार पर पी.पी.एफ. स्कीम में एजेन्टों को मिले वाला 1 (एक) प्रतिशत का कमीशन समाप्त कर दिया गया है तथा डाक बचत योजनाओं में इस कमीशन को कम कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश के लाखों एजेंटों की आय पर संकट निर्माण हो गया है। इस विषय को पिछले बजट सत्र में भी उठाया गया था परंतु वित मंत्री महोदय द्वारा नीतिगत विषय कहते हुए इसे टाल दिया गया। छोटी-छोटी बचतों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है तथा इन बचतों को आम आदमी के बीच लोकप्रिय बनाने में एजेंटों का बड़ा योगदान है। इन एजेंटों द्वारा लघु बचत की विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से किए जा रहे परिश्रम को नजरअंदाज करना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि एजेंटों का कमीशन पहले की भांति प्रदान किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।